



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

सेवा में

1. सभी उपायुक्त (हरियाणा राज्य में)।
2. प्रबन्धक निदेशक, हैफेड, कारपोरेट ऑफिस, सैक्टर-5, पंचकूला।
3. प्रबन्धक निदेशक, स्टेट वेयर हाउससिंग कारपोरेशन, पंचकूला
4. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा रिजन, बेस न0 29-32, सैक्टर-4, पंचकूला।
5. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक (हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांक: एम0पी-1/3/2025/2663

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

विषय:- रबी तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की फसलों के लिए परिवहन कार्यों हेतु (ई-टैण्डरिंग के माध्यम से) परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति करने बारे पोलिसी।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सामान्य शर्तें

1. रबी तथा खरीफ वर्ष 2024-25 की फसलों की हैण्डलिंग के लिए नियुक्त किये गये परिवहन ठेकेदारों की कार्यावधि दिनांक 31.3.2025 को समाप्त होने जा रही है। हरियाणा राज्य की सभी मण्डियों में वर्ष 2025-26 में रबी तथा खरीफ की फसलों के परिवहन के लिए नये सिरे से ई-टैण्डरिंग के माध्यम से परिवहन ठेकेदार नियुक्त करने की कार्यवाही शीघ्र की जानी है। इस सन्दर्भ में जिला स्तर पर भी खुला प्रचार किया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर खुला प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों में, सभी सम्बन्धित कार्यालयों जैसे कि सभी खरीद एजेंसीयों, मार्किट कमेटी, नगर पालिका, पंचायत घरों व खरीद केंद्रों आदि के नोटिस बोर्डों पर टैण्डर नोटिस को चस्पा कर करें। जिलावार टैण्डर आमंत्रित करने के लिए टैण्डर नोटिस की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। खरीद किए गए खाद्यान्नों जिनका भण्डारण 8 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा, उसका परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। गेहूं की मण्डी से भारतीय खाद्य निगम को सीधी डिलीवरी के लिए unloading का कार्य FCI द्वारा किया जाएगा।

2. विषयाधीन टैण्डर के माध्यम से नियुक्त किये गये परिवहन ठेकेदारों द्वारा खरीद किये गये खाद्यान्नों के 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर स्थित भण्डारण/प्रेषण हेतु परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदारों द्वारा किया जाना है, जिसके उठान हेतु पर्याप्त लेबर श्रम व ढुलाई ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद्यान्नों को मण्डी स्थल से 8 किलोमीटर तक के दायरे में स्थित भण्डारण स्थलों तक पहुंचाने हेतु परिवहन कार्य श्रम व ढुलाई ठेकेदार द्वारा किया जाएगा जिनके लिए अलग से टैण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं।

3. पूर्व वर्षों की तरह परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिए जिला मुख्यालय पर टैण्डर आमंत्रित करने तथा इनके अन्तीकरण के लिए जिला टैण्डर कमेटीयों का गठन निम्न प्रकार से किया गया है तथा कमेटी का कार्य टैण्डर की शर्तों में व्याखित किया हुआ है:-



Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

क्र०	पदनाम	पद
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक या उन द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
3	उप मण्डल अधिकारी (ना०), जिला मुख्यालय	सदस्य
4	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक,	सदस्य सचिव
5	भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य की सभी खरीद एजेंसियों के जिला प्रबन्धक	सदस्य

4. (I) वर्ष **2025-26** की रबी तथा खरीफ की फसलों के परिवहन कार्यों के बेसिक दरों (S.O.R.) का विवरण साथ संलग्न है, इसलिए टैण्डरदाताओं द्वारा इन बेसिक दरों पर अपने टैण्डर में परिवहन कार्यों के दर quote किये जाने हैं।

(II) वर्ष **2025-26** के लिए नियुक्त किये जाने वाले परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियों बारे टैण्डर की शर्तें एवं बेसिक दरें (SOR) साथ संलग्न की जा रही हैं। टैण्डर की शर्तों में उक्त व्याखित तथ्यों के ईलावा अन्य तथ्य, जिन के अनुसार टैण्डर आमंत्रण तथा इनका अन्तीकरण किया जाना है, विस्तृत रूप से व्याखित किये गये हैं। अतः टैण्डर कमेटी "टैण्डर आमंत्रण एवं उन का अन्तीकरण" टैण्डर की शर्तों अनुसार करने की कार्यवाही करें जोकि टैण्डर प्रक्रिया का ही भाग होगा। सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक/राज्य की खरीद एजेंसियों के जिला प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों से टैण्डर की शर्तों अनुसार "इकरारनामा" (on proper stamp paper) किया गया है तथा उन द्वारा हस्ताक्षरित (प्रत्येक पृष्ठ) टैण्डर की शर्तें, इकरारनामों के साथ रखी गई हैं।

(III) वर्ष **2025-26** में परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए कुछ pre-qualification conditions निर्धारित की गई है जो की संलग्न "Terms and Conditions" में उल्लेखित की गई है।

(IV) वर्ष **2025-26** के दौरान खरीद की गई फसलों को मण्डी से ट्रकों में लदाई करके गोदामों/राईस मिल में भण्डारण से पूर्व प्रत्येक ट्रक की तुलाई सम्बन्धित जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकृत उचित धर्मकांटे पर करवानी आवश्यक होगी। खरीद की गई फसल के तोल की समानता व सहीपन की सुनिश्चितता के लिए जिला नियन्त्रकों को अधिकृत किया जाता है कि वे धर्मकांटों की सूची मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा सम्बन्धित निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान से प्राप्त करें व list पर सम्बन्धित उपायुक्त की prior approval लेकर स्वीकृतियां जारी करें जिन पर खरीद की गयी गेहूं की तुलवाई करवाई जानी है।

(V) रबी तथा खरीफ खरीद सीजन **2025-26** के दौरान फसल की खरीद के 24 घण्टे के अंदर आदती को फसल का उठान के लिए ऑफर करना है।

(VI) यदि परिवहन ठेकेदार, समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे तो उन पर पैनल्टी लगाई जाएगी। यदि परिवहन ठेकेदार 3 घण्टे की समय सीमा में ट्रक उपलब्ध नहीं करवाएगा तो उस पर पैनल्टी लगेगी। यह सारी प्रक्रिया ई-खरीद पोर्टल पर रिकार्ड की जाएगी।

5. All the tenders shall be opened in the presence of the Chairman and all the members including Member-Convener of the District Level Tender Committee. The Chairman and all the members of District Level Tender



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

Committee (DLTC) will sign (along with date and designation) the tender form before and after finalization of the tender. The tender shall also be signed by the tenderer with the full name of the tenderer written below signature. Final rate decided by the Committee shall also be written in words.

6. As per the Government of India guidelines dated 06.05.2019, uniform SOR for the fixation of Transportation charges and finalization of economic cost will be decided by State Level Committee (SLC).

Further, Provision explained in clause No. 25.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार केन्द्रवार परिवहन दरों की स्वीकृतियां सम्बन्धित जिला उपायुक्त के अनुमोदन उपरान्त जारी करने हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें और तत्पश्चात् मुख्यालय को इस स्वीकृति की प्रति/आवश्यक सुझाव (यदि कोई हों) भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे परम अग्रता प्रदान करें।

संयुक्त निदेशक (मंडी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: एम०पी-1/3/2025/2664

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की प्रति हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वर्ष 2025-26 की खरीफ की फसलों की परिवहन के लिए परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिये तैयार की गई टैण्डर की शर्तें तथा इकरारनामे व टैण्डर नोटिस के प्रारूप की प्रति भी साथ संलग्न की जाती है।

संयुक्त निदेशक (मंडी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: एम०पी-1/3/2025/2665

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल, फरीदाबाद एवं गुड़गांव को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (मंडी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: एम०पी-1/3/2025/2666

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (State Informatic Officer), एन.आई.सी., न्यू सचिवालय, हरियाणा, चण्डीगढ़।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. को इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि राज्य के सभी जिलों के डी.आई.ओ. को ऑनलाईन ई-टैडरिंग के कार्य व्यवस्था के उचित संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

संयुक्त निदेशक (मंडी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ0 क्रमांक: एम0पी-1/3/2025/2667

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को माननीय राज्य मंत्री, खाद्य एवं पूर्ति महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं पूर्ति तथा निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ सचिव/माननीय राज्य मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
2. वरिष्ठ सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

संयुक्त निदेशक (मंडी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

Terms and Conditions of Transportation E-Tenders Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana.

1. Contractor/Tenderer should not have been blacklisted by any of the Department/Semi Government Organization of the State Government and by FCI, and not connected to any firm which has been so blacklisted.

Note:- The term 'Contractor' shall mean and include the person(s), Firm or Company with whom the contract has been placed including their heirs, executors, administrators and successors and the permitted assignees as the case may be.

2. Submission of the e-Tender documents: The tenderer shall have to deposit an amount of Rs. 1000/-plus 18% GST i.e. totaling Rs. 1180/- e-tender fees which is non-refundable.
3. The tender shall start on **dated 24.02.2025 at 9:00 AM** and close on **03.03.2025 at 5:00 PM**.
4. Opening of e-Tender: Technical bids shall be opened on **dated 04.03.2025 at 9:00 am** and the financial bids of the tenderers who qualify in the Technical Bids shall be opened on **dated 06.03.2025 at 2:00 PM**. These Bids shall be opened at respective district offices in the presence of the tenderers who may be present.
5. Tenderers should submit both the tender bids i.e. "Technical Bid" and "Financial Bid" only in Electronic form (Refer Tender documents). Financial Bid Proposal shall be submitted mandatorily online under commercial envelope and original not to be submitted manually). Financial Bid will be opened only after complete evaluation of Technical Bid.
6. **A tenderer/contractor should not be allotted more than 3 mandis in each district.**
7. Each Technical Bid must be accompanied by an earnest money i.e. 5% of the total cost of contract of previous year, of mandi for which tender is to be submitted through RTGS as per bank details given below:-

Name of beneficiary	District Food & Supplies Controller
Account No.	
Name of Bank	
IFSC Code	

8. Tender form not accompanied with the requisite amount of earnest money will be out rightly rejected. The amount of earnest money of the unsuccessful tenderers will be refunded within 5 working days from the date of tender except that of L2 & L3 whose EMD will be refunded within 15 working days from the date of finalization by the tender.
9. The following documents are required with Technical bid:-
 - i) Certified copy of Partnership Deed/Registration of Firm.
 - ii) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

- iii) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
- iv) Solvency certificate issued by the banker.
- v) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of the preceding 3 financial year's i.e. **2021-22, 2022-23 & 2023-24.**
- vi) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value.
- vii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender and for balance he/she may have agreement with any transport company/truck owners with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ **Rs 1,25,000/- (75,000 refundable + 50,000 non-refundable)** per trucks of short no of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. **However this relaxation would be given only for 10% of the shortage in owned trucks.** The additional **refundable** security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points. If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3, L-4, L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. The same will be applicable for all the tenderers. The requirements of trucks are as under:-

Class of Mandi	Arrival/Procurement	No. of Trucks required
A	Upto 10000 MT	10
B	From 10001 MT to 20000 MT	20
C	From 20001 MT to 40000 MT	30
D	From 40001 MT and above.	40

Note:-1) Price bid will be opened only if the tenderer qualifies in the technical bid.

Note:-2) Previous/Projected Procurement figures of Rabi & Kharif crops may be taken from the office of the DFSC/DM concerned of the agency in District.

Note A. Copies of Registration Certificates of all the trucks mentioned in the above list along with copies of verification report generated from e-parivahan portal shall be submitted to the District Level Tender Committee on the spot (i.e. at the time of evaluation of Technical bid).



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

- Note B. If the registration certificates of trucks submitted by the tenderer is/are found to be invalid (i.e. RCs have expired and have not been renewed etc.) capacity of the invalid vehicles shall be deducted accordingly and tender of the tenderer shall be liable to be rejected/ cancelled, if the required capacity of the relevant Mandi is not met.
- Note C. During the procurement season, provision/option to add/remove the transporter details along with the vehicle detail is already available in e-kharid. Procurement Agency can unmap their respective transporter from the Mandis after closure of the respective mandi to enable his mapping as per requirement.
10. Conditional tenders will not be entertained and shall summarily be rejected by the Distt. Tender Committee.
11. **If any tenderer uploads false/wrong documents while applying the tender. DLTC (District Level Tender Committee) has the authority to initiate suit for civil/criminal proceedings against the said tenderer/Contractor.**
12. a) The District Level Tender Committee reserves the right to negotiate as per Directorate of Supplies & Disposal, Govt. of Haryana Notification No. 2/2/2010-4-IB-II dated 16th June 2014 and Finance Department, Haryana letter no. 14/26/2023&6FA, dated 10.05.2023 and finalize three transport agencies in a few selected mandies where the arrival is more than 50,000 MT (list attached) where all the selected agencies can work simultaneously at the lowest negotiated rates. In case of mandies where the arrival is more than 25000 MT and **upto** 50,000 MT (list attached). The Committee will finalize two transport agencies who can work simultaneously at the lowest negotiated rates. In case, the Tender Committee considers that the negotiated rates are not reasonable/ competitive/ workable the Committee may consider cancelling and re-inviting the tenders.
- b) If there are two or more procuring agencies in a mandi, District Tender Committee should first finalise the rates of that procuring agency for which the lowest rate is quoted. Thereafter, the bidders for other agencies should be encouraged to work at the finalised rate if they do not agree, District Tender Committee reserves the right to allot the full mandi to the finalized lowest bidder of the other procuring agency.
- The following provision has been made as per instructions of Finance Department, Haryana letter no. 14/26/2023&6FA, dated 10.05.2023:-
- c) However, negotiation could be held upto four number of such bidder(s), in addition to L1 bidder in cases where there are bidders falling within 5% of the L1 bidder. In cases where the L1 bidder refuses to further reduce his offered price and any of the four bidders come forward to offer a price which is better than the price offered by L1 bidder, whose price is accepted becomes the L1 bidder.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

However, in such a situation, the original L1 bidder may be given one more opportunity to improve upon the discovered price. In case, the original L1 bidder further improve upon the price discovered during the negotiations, he would be treated as the L1 bidder.

- (d) In cases where there is no bidder within 5% of the L1 bidder:-
L2 Bidder will be invariably called for negotiation in addition to the L1 bidder.
L3 bidder will also be called, if it is so decided by the Minister-In-Charge, in addition to L1, L2 bidder.
13. The Distt. Tender Committee reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. After the final acceptance of the tender by the tender committee, no request for further increase of rate for any operation shall be entertained.
14. The successful tenderer shall deposit the amount of security i.e.10% of the total cost of contract of previous year within three working days of the acceptance of his tender by the Tender Committee. In case of jointly operated mandi, the security will be deposited in the office of the DFSC. Where the mandi is operated exclusively by any agency, the security shall be deposited with the DFSC/DM of the concerned agency. The earnest money deposited by the successful tenderer as above shall be adjusted in the security amount.
15. The successful tenderers will execute an agreement on a stamp paper with the DFSC/DM concerned agencies within five working days of the acceptance of his tender. He/she/they shall also furnish two sureties each of equal amount of security, as above, from two reputed local persons possessing sufficient immoveable property. In case of his/her/their failure to do so, the amount of earnest money shall stand forfeited and he/she/they will be black-listed as well as debarred from taking any work of the State Procurement Agencies in future.
16. In case the lowest tenderer fails to deposit the requisite amount of security and to fulfill requisite formalities as above, the DFSC/DM of the concerned Agency will be competent to make an offer to the next lowest tenderer L2 & L3 with prior concurrence of the concerned Deputy Commissioner. In this regard, the following clauses are included:-
- (a) Earnest money of two other lowest bidders (L2 and L3) should be kept pending for 15 days so that in case of default of first tenderer, quotes of L2 and L3 can be considered.
- (b) Offers will be made to L2 to work at L1 rates in the eventuality of L1 not being able to work as per the terms and conditions. In case L2 is willing to work at L1 rates, he will be allotted the balance work. In case of unwillingness of L2, offer will be made to L3 to work at L1 rates. In case L3 is willing, L3 will be allotted the work at L1 rates. If L3 is not willing, then negotiation will be held with L2 at his quoted rates and if the rates of L2 are unreasonable, the authorities will be free to make a counter offer to L2 and if this is not accepted the discussions with L2 will be terminated and similar negotiations will be entered with L3. The



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

authorities may quote a counter offer here also as in the earlier case if L3 rates are unreasonable or the subsequent rates quoted by L3 are felt to be unreasonable or high. In case there is no acceptance of counter offer or if the rates in negotiations are too high, the committee may cancel the tender. Fresh local tenders will be called, if necessary, giving 24 hours notice.

- (c) However, any new contract, in case of any emergency will be awarded only after the emergency or urgency is properly justified by District Tender Committee headed by the Deputy Commissioner and approval of Director Food, Civil Supplies and Consumer Affairs is taken for this.
- (d) There will be no earnest money requirement for new contracts in case the earlier contract is cancelled on the above account.
17. If the successful tenderer, after depositing security amount, resiles from his offer and does not come forward for entering into an agreement with the concerned Procurement Agency within the stipulated period, then his security amount shall stand forfeited and DFSC/DM shall be at liberty to get the work done at his risk and cost.
18. If the successful tenderer after depositing security amount and entering into an agreement with the concerned DFSC/DM, fails to undertake the work or refuses to work or make default in proper fulfillment of the conditions of the Agreement, or leave the work in between, the security deposited by him shall stand forfeited and he will be black listed besides being debarred from allotment of any work of the State Procurement Agencies in future. In addition the DFSC/DM concerned agency shall be competent to get the remaining work carried out on the prevailing market rates/ by appointing regular contractors at the risk and cost of the defaulting transporter by serving him with one day's notice and in that case extra amount incurred by the Department/Agency shall be recoverable from the defaulting transporter from his security and pending bills. In case any amount still remains recoverable, that would be recovered from the two sureties given by the transporter. In case the recoverable amount from the defaulting transporter still remains after the above adjustment, the exceeded amount shall be recovered from the defaulter transporter as arrears of land revenue.
- a) No interest shall be paid on security deposit.
19. Successful tenderer will have to start the work as and when asked by the DFSC/DM of the Agency and is required to provide sufficient number of trucks as required by the Inspector-in-Charge/Purchaser of the centre, as per terms and conditions of the tender, within a time limit of 3 hours after the purchase. **As the stock gets ready to lift by Arthiya and verified by Inspector-in-charge/purchaser of the centre, contractor will be get the information on his login ID. Contractor will be required to provide trucks immediately and lift the stocks within 48 hours. The login Id's of the contractors will be shared by concerned DFSC/DM after allotment of tender. In case the contractor fails to provide sufficient number of trucks as per terms and**



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

conditions of tender, Rs.5,000/- per truck will be charged as penalty on the remaining stocks. The shortage in food grains, if any, shall be borne by the Arthiya if found after first weighment (at mandi or weighbridge assigned to the concerned mandi), and by the transporter, if found after second weighment (at the storage point).

20. Transporter is also required to transport food grains/coarse grains/stock articles from mandis/storage points as the case may be on the directions of the DFSC/DM of the concerned agencies. In addition he/she/they also will be responsible to compensate any loss caused to the Procurement Agencies for non delivery of stocks of food grains/coarse grains and stock articles at destination in time. Services of any other source will be utilized by the Department/Agency without issuing any notice to the transport contractor and payment of such operations carried out by such Company, will be made by the procuring Agency directly to that Company and the transport contractor shall have no objection or claim in this regard. By utilizing the services of such standby Company, the transport contractor will not be absolved of his liabilities/obligations under the risk and cost clause above for food grains lifted by engaging any other person/mode of conveyance. The extra expenditure payable by the procuring agency shall be recoverable from the defaulting transport contractor in due course and as per terms and conditions of risk and cost as specified above. If trucks are not supplied as per demand, besides the penalty, the security amount may be forfeited. In such a case, a short notice will be issued to the defaulting transport contractor and in case of proven default/deficiency in service, the security deposited by him shall stand forfeited and he will be black listed besides being debarred from allotment of any work of the State Procurement Agencies in future.
21. The transporter should arrange VLTD (Vehicle location and Tracking Device) of AIS 140 standard as notified by MORTH on all the trucks. These VLTDs trackers shall be monitored with the assistance of a third party service provided. Movement of food grains (Wheat, Bajra, Paddy, Rice etc.) from mandis/rice mills to storage points of agencies and FCI godowns will be tracked. Hence, it is to be ensured that vehicles used for the purpose have functional VLTDs which should be registered and integrated with Software/Mobile App/Portal of service provider selected for the purpose and e-Kharid Portal. VLTD manufacturer should integrate with the Selected System Integrator (SI) for the RMS & KMS season 2025-26.
22. The transporter shall have to execute all the work to the full satisfaction of the Department/Agency. Directions for proper execution of the contract or for speedy and careful handling of food grains and stock articles, issued in this behalf by DFSC/DM or his representative shall be binding on him. Transporter shall have no objection for utilizing the services of own vehicles by



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

Govt./Agencies/Societies of any procurement agency/DFSC for procurement/lifting of stocks and stock articles.

23. The successful tenderer shall be liable to do the job of transportation work for the stocks/stock articles being received/sent from/to other centers anywhere in the State. The successful tenderer will be governed by the laws of India for the time being in force.
24. The successful tenderer shall take adequate steps and necessary precautions to avoid wastage, damage and shortage of the food grains/coarse grains/stock articles during its handling and transportation. The transporter shall be liable for any loss which the agency may suffer on account of the above account. He/she/they will be responsible for any kind of shortage of food grains/coarse grains/stock articles in transit. He will also incur all charges viz. transportation, and toll tax etc.
25. a) All the tenders with premium upto 10% of the SOR shall be accepted at the level of District Level Tender Committee (DLTC).
b) If the premium is higher than 10% even after re-tendering, then the proposal should be sent to the SLC for consideration/approval.
c) No payment shall be made to the tenderer, (in case, the premium is higher than 10%) prior to the approval of rates by the State Level Committee. All payments shall be made by the concerned DFSCs/DMs of the Procuring Agencies as per the provisions of the policy.
26. All persons employed by the transporter shall be engaged by him as his own employees/workers in all respects and the responsibility under the Indian Factories Act or the Workmen's Compensation Act 1923 or Employees Provident Fund Act or any other similar enactments in respect of all such personnel/labour shall be only that of the transporter. The transporter shall be bound to indemnify the agency against all claims whatsoever in respect of the said personnel/labour under the Workmen's Compensation Act 1923 or any statutory modification thereof or otherwise in respect of any damage or compensation payable in consequence of any accident or injury sustained by any workmen or other person whether in employment of the transporter or not. A monthly report about the statutory compliance will be given by transporter to DFSC/DM concerned.
- a) The Contractor shall comply with all the guidelines and instructions of Labour Department issued vide letter No. 2189-2330 dated 18.01.2019, letter No. HLWB/8666-8816 dated 17.09.2018 and guidelines issued by the Chief Secretary, Haryana vide their office letter No. 43/5/2001-3GS-II dated 20.02.2014 and all other instructions issued from time to time in this regard.
27. **In respect of overloading Contractor shall comply with the section 113 of The Motor Vehicle Act, 1988.**
28. The security will be refunded after the successful execution of the contract and after completion of internal audit of accounts for that period and if nothing is found due against him. The security in respect of joint mandi shall be released by



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

the DFSC concerned after obtaining "no dues certificate" from the DM of the agencies concerned.

29. Deduction of Income Tax and surcharge, if any, applicable shall be made at source as per law. It shall be the responsibility of the contractor to comply with the provisions of the Income Tax Act.
30. In case any dispute arises between the transporter and State Procurement Agencies, the matter will be referred to the Director, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Haryana/ Managing Director of the agency concerned or his nominee to adjudicate the matter of dispute under the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and his decision shall be binding on both the parties.
31. **In case of penalty the contractor present his appeal before First Appellate Authority i.e. DLTC if the contractor does not agree/ satisfy with the decision of DLTC then the contractor may submit his appeal before the Second Appellate Authority i.e. Director General/Director Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana/MD,HAFED/MD, HSWC.**
32. Tenderer may clearly mention his/her bank account no., name of bank and its branch along with IFSC code for refund of EMD and for transportation charges payment in proforma 'x' given with technical bid value as per notification issued by concerned State Govt. from time to time.
33. No interest shall be payable on EMD.
34. Any participant, who is recognized and registered as startup with department for promotion for industries and internal trade (DPIIT) and apply for MTC tender will be considered as per provision of startup policy and guidelines issued by the Industries and Commerce Department Haryana.

Signature
13/2/25

Joint Director (Mandi Proforma)
for Director, Food, Civil Supplies and
Consumer Affairs Department Haryana



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

PART- I

Scheduled of Rates (SOR) of Transportation Charges for the year 2025-26 fixed by the State Level Committee (SLC) vide memo no. SOMP-3/3/2023/2059-60 dated 08.02.2023 are as under:-

		SOR for the year 2025-26
S. No.	Distance	Rate per Quintal (in Rupees)
1	0 to 8 K.M.	Rs. 14.3
2	8 to 20 K.M.	Rs. 0.37 per K.M. in addition to Rs. 14.3
3	20 to 40 K.M.	Rs. 0.28 per K.M. in addition to Sr. No. 1 & 2 above.
4	40 to 80 K.M.	Rs. 0.19 per K.M. in addition to Sr. No. 1 to 3 above.
5	80 K.M. & above	Rs. 0.24 per K.M. in addition to Sr. No. 1 to 4 above.

Lowest Tender rates offered/ recommended (with the name of party).	Detail of efforts made to bring down the transportation rates by the committee.	Recommendation of the DC for the year 2025-26.	RTA rates.	Approved rate.	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

Proforma of Agreement

1. This agreement is made on _____ day of _____ month of _____ year between Sh./M/s _____ (hereinafter called the first party and DFSC/DM/Manager of the FCI and the concerned State Procurement Agency (hereinafter called second party).
2. The first party agrees to work as transport contractor in respect of _____ mandi for doing various transportation works as per terms of the tender (enclosed).
3. That the second party has given approval of the rates given as under for which first party has agreed to work on such rates.
 Part-I As per schedule rate
 Part-II _____ %age above/below/at par of schedule rate
4. This agreement is valid upto **31.3.2026**.
5. In case any dispute arises between the contractor and the State Procurement Agency, the matter will be referred to the Director/Director General Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Haryana /Managing Director of the concerned agency or his nominee for adjudicating the matter of dispute under the provisions of Arbitration Act, 1996 and his decision shall be binding on both the parties.

Executants

1st Party

2nd Party

Witnesses :

1.

2.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

E-TENDER NOTICE FOR TRANSPORTATION OF FOODGRAINS/ COARSE GRAINS/OIL SEEDS/PULSES/STOCK ARTICLES ETC. FOR THE YEAR 2025-26.

The e-tenders are invited from various Transporters and Transport Unions for transporting the food grains/coarse grains/oil seeds/Pulses/stock articles etc. from mandi/storage points in the District/outside the District for the year **2025-26** in respect of State Procurement Agencies i.e. Food Civil Supplies & Consumers Affairs Department, Haryana State Co-operative Supply & Marketing Federation (Hafed), Haryana State Warehousing Corporation (HSWC) and Food Corporation of India (FCI). The tenders in respect of all the Agencies shall be received by the concerned Deputy Commissioner/Tender Committee/DFSC as follows:-

Invitation of Tender	24.02.2025 at 09:00 am
Closing date of Tender	03.03.2025 till 05:00 pm
Opening of Technical Bid	04.03.2025 at 09:00 am
Opening of Financial Bids and finalization of Tender by DLTC	06.03.2025 at 02:00 pm
Re-tender (if any)	10.03.2025 at 09:00 am
Opening Date	
Closing date of re-tender	17.03.2025 till 05:00 pm
Opening of Technical Bids	18.03.2025 at 09:00 am
Opening of financial Bid and finalization of re-tender/ send proposal to SLC for finalization by DLTC (if, the premium is higher than 10%) after re-tendering	19.03.2025 at 09:00 am
Finalization of rates by SLC	26.03.2025

- If single tender is received in any mandi, re-tender will be called on very next day after closing date of the invited tender.
- If even after re-tendering twice, single tender is received for the third time, then the decision regarding opening of bid and finalization of tender on single bid as per Clause 25, may be done by DLTC.

1. The venue for receiving/opening of tenders shall be fixed by the concerned Deputy Commissioner/ Tender Committee as per details given in the tender notice.
2. Tender Form and detailed terms and conditions can also be downloaded from the Website i.e. <http://etenders.hry.nic.in>.
3. In case of any enquiry/problem, the District Food and Supplies Controller of the concerned District may be contacted.
4. The procurement figures of wheat, paddy pulses, mustard, mustard oil and coarse grain purchased during Rabi & Kharif Marketing Season for the year 2024-25 (if required) can be obtained from the concerned agency on any working day.



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

5. The Distt. Tender Committee reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. After the final acceptance of the tender by the tender committee, no request for further increase of rate for any operation shall be entertained.

Onkaran
2

Negama
13/2/25

Joint Director (Mandi Proforma)
for Director, Food, Civil Supplies and
Consumer Affairs Department Haryana



Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

FORMAT OF TECHNICAL BID (FOR TRANSPORTATION TENDER 2025-26)

Sr. No.	Particulars	
1.	<p>Detail of the duly self attested Certificate to be uploaded: (Yes/No)</p> <p>i) Certificate on proper stamp paper that the contractor/tenderer has not been blacklisted by any of the Government/Semi Government Department of the State & by FCI, and not connected to any blacklisted firm.</p> <p>ii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender and for balance he/she may have agreement with any transport company/truck owners. If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3, L-4, L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ Rs 1,25,000/- (75,000 refundable + 50,000 non-refundable) per trucks of short number of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. However this relaxation would be given only for 10% of the shortage in owned trucks. The additional refundable security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points. The same will be applicable for all the tenderers. (As per terms and conditions).</p> <p>iii) Certified Partnership Deed in case of partnership concerns.</p> <p>iv) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.</p> <p>v) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.</p> <p>vi) Letter from the bank regarding credit/limits enjoyed.</p> <p>vii) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of the preceding three financial year's i.e. 2021-22, 2022-23 & 2023-24.</p>	



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

	viii) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value.	
2.	Detail of Earnest Money Deposit and for transportation charges payment	RTGS...NO DATE.... NAME OF BANK..... AMOUNT.....
3	Whether the copies of the following documents duly signed at each page have been uploaded (write Yes or No)	
	i) Tender Documents and Terms & Conditions. ii) Power of attorney to sign the tender documents.	

M

Ankur
js



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

टैन्डर फार्म
 परिवहन कार्य हेतु
 वर्ष 2025-26

टैन्डर नोटिस क्रमांक:

दिनांक

1. टैण्डरदाता व पार्टी का नाम
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थाई पता (as per voter list/ration card/identity card/licence)
5. केन्द्र का नाम जिसके लिए टैण्डर दिया जाना है
6. धरोहर राशि
7. बैंक का नाम आर टी जी एस राशि
8. मोबाईल नं० ई०-मेल आई०डी०

Affix attested
 Passport Size
 Photograph of
 Tenderer

सेवा में

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक,

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैंने/हमने उपरोक्त टैन्डर नोटिस की सभी धाराओं का तथा उसके साथ सभी संलग्न दरों का भली भांति अध्ययन कर लिया है और मैं/हम उपरोक्त वर्णित केन्द्र पर उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए परिवहन का कार्य दर्शाई बेसिक दरों पर निम्नलिखित टैन्डर दरों पर करने के लिए सहमत है/हूँ :-

1. प्रतिशत उपर (ASOR)
- 2- बेसिक दर (SOR)
- 3- प्रतिशत कम पर (BSOR)

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम अथवा मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी/सोसाईटी किसी भी विभाग/एजेंसी के कार्यों के लिए ब्लैकलिस्टिड नहीं है व ना ही मेरा किसी ब्लैकलिस्टिड फर्म से सम्बंध है ।

हस्ताक्षर टैण्डरदाता

कार्यालय उपयोग के लिए

तकनीकी बोली में सफल होने उपरांत टैण्डरदाता का टैण्डर फार्म निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में खोला गया

जि.प्र. जि.प्र. जि.प्र. जि.खा.पू.नि. एवं उ.म०अ०(ना०) पुलिस अधीक्षक
 एफ.सी.आई हैफेड एच.डब्ल्यू.सी. जि.प्र. कान्फैड

उपायुक्त/प्रतिनिधि उपायुक्त



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

List of mandis where the purchase of Wheat between 250000 to 50000 MT by the procurement agencies		
Sr. No.	DIS_NAME	Mandi Name
1	Panipat	Matlauda
2	Jhajjar	Beri
3	Karnal	Jundla
4	Rohtak	Sampla
5	Sirsa	Dabwali
6	Jhajjar	Jhajjar
7	Yamunanagar	Radaur
8	Sonipat	Kharkhoda
9	Yamunanagar	Jagadhri
10	Palwal	Hodal
11	Hissar	Bas
12	Sirsa	Rania
13	Yamunanagar	Mustafabad
14	Bhiwani	Bawani Khera
15	Yamunanagar	Chhachhrauli
16	Hissar	Narnaund
17	Palwal	Palwal
18	Fatehabad	M.P.Rohi
19	Jhajjar	Majra D
20	Sirsa	Bani
21	Hissar	Adampur
22	Palwal	Hasanpur
23	Panipat	Panipat
24	Hissar	Bandaheri
25	Panipat	Bapoli
26	Jind	Alewa
27	Sonipat	Gannaur
28	Panipat	Israna
29	Sonipat	Sonipat
30	Ambala	Naraingarh
31	Palwal	Hathin
32	Yamunanagar	Bilaspur
33	Gurugram	Jatauli (Haily Mandi)
34	Ambala	Barara
35	Jind	Naguran
36	Rohtak	Lakhanmajra
37	Kurukshetra	Pipli
38	Kurukshetra	Babain
39	Sirsa	Kharia
40	Sirsa	Jiwannagar
41	Kurukshetra	Thol
42	Karnal	Kunjpura



Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

List of mandis where the purchase of Wheat more than 50000 MT by the procurement agencies		
Sr. No.	DIS_NAME	Mandi Name
1.	Kurukshetra	Thanesar
2.	Jind	Julana
3.	Karnal	Assandh
4.	Karnal	Taraori
5.	Hissar	Barwala(H)
6.	Karnal	Nissing
7.	Rohtak	Rohtak
8.	Jind	Safidon
9.	Jind	Jind
10.	Kurukshetra	Ladwa
11.	Kurukshetra	Pehowa
12.	Kurukshetra	Ismailabad
13.	Sirsa	Kalanwali
14.	Karnal	Gharaunda
15.	Karnal	Karnal
16.	Hissar	Hansi
17.	Panipat	Samalkha
18.	Jind	Uchana
19.	Jind	Narwana
20.	Karnal	Nigdhu
21.	Fatehabad	Fatehabad
22.	Fatehabad	Bhuna
23.	Fatehabad	Ratia
24.	Karnal	Indri
25.	Rohtak	Meham
26.	Jind	Pillukhera
27.	Ambala	Ambala City
28.	Sirsa	Sirsa
29.	Kaithal	Kalayath
30.	Kaithal	Solu Majra (Silo)
31.	Kaithal	Cheeka
32.	Fatehabad	Tohana
33.	Faridabad	Mohna
34.	Kurukshetra	Shahbad
35.	Kaithal	Extension Grain Market Kaithal
36.	Hissar	Uklana
37.	Kaithal	New Grain Market Kaithal
38.	Yamunanagar	Khizrabad (Partap Nagar)
39.	Sirsa	Ellenabad
40.	Sonipat	Gohana